with under Rule 11 of the Centre Services (Medical Attendance) Rules, 1944, according to which a Government Servant is eligible for treatment abroad on the recommendation of the Standing Committee of Medical Experts set up for the purpose under the said Rules The scale of expenditure and the eligibility for treatment for which a Govt. Servant or a member of his family shall be entitled, shall be identical to the scale of expenditure and the eligibility of an official of the Indian Foreign Service of the corresponding grade in the Ministry of External Affairs under any Assisted Medical Attendance Scheme for the time being in force.

(c) and (d) Since recognition of private hospitals with latest technology have taken place only since 1996-97, under CGHS/CS(MA) Rules, 1944, it is too early to assess its impact.

Opening of a CGHS Dispensary in Vikaspuri

972. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no CGHS dispensary in Vikaspuri and a large number beneficiaries of that area have been attached with Dispensary No. 61 in Janakpuri;

(b) whether Government propose to open a CGHS dispensary in Vikaspuri; if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;

(c) the total number of CGHS beneficiaries/card holders attached with Dispensary No. 61 in Janakpuri; and

(d) whether the number of card holders at this dispensary is more than what is prescribed as per the rules/ orders?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) and (b) Residents of Vikaspuri are covered by the nearest CGHS Dispensary at Janakpuri for availing CGHS facilities.

Depending on the feasibility, requirements, availability of resources etc. and subject to fulfilment of CGHS norms, the CGHS network is being expanded gradually. However, it is not possible to open a dispensary for each cluster of CGHS beneficiaries.

(c) The total number of card holders/ beneficiaries registered in the CGHS dispensary No. 61 Janakpuri are 11,575/ 48,000 approximately.

(d) Under the prescribed rules/orders, a mimimum number of 2,500 card holders are required to open a new dispensary in a locality covering the area of 4-5 Kms. radius, but there are no fixed norms for maximum number of cards.

औषध परीक्षणशालाओं का बंद होना

973. **श्रीमती मालती शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में किसी औषध परीक्षणशालाएं है और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि देश में अनेक औषध परीक्षणशालाएं बंद पड़ी है,

(घ) सरकार इन्हें, पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी) : (क) राज्य/संधराज्य क्षेत्र सरकारों के नियंत्रण में 19 जांच प्रयोगशालाएं है जबकि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में 5 जांच प्रयोगशालांए हैं ।

इन प्रयोगशालाओं की संख्या और ये कहां-कहां स्थित हैं, को दर्शानें वाली जानकारी विवरण में दी गयी है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पटना स्थित राज्य सरकार की जांच प्रयोगशाला पिछले 20 वर्षों से कार्य नहीं कर रही है ।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार पटना में बिहार राज्य की जांच प्रोगशाला का भवन भूतल पर हर वर्ष

वर्षऋतु के कारण पानी जमा हो जाने के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त हालत में हैं । इसलिए प्रयोगशाला को बिहार सरकार द्वारा पर्याप्त उपकरण और विशेषज्ञ जांच कार्मिक मुहैया नहीं कराए गए हैं ।

(घ) बिहार सरकार से प्रयोगशाला को पुनः शुरू करने के लिए भवन के ढांचे में सुधार करेन अथवा अपेक्षित उपकरण और कार्मिक शक्ति मुहैया कराने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

विवरण

राज्य सरकार की औषध जांच प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय सरकारी औषध जांच प्रयोगशालाओं के राज्यवार नाम, संख्या और वे कहां स्थित हैं,

राज्य का नाम	केन्द्रीय प्रयोगशाला	राज्य प्रयोगशाला
आंध्र प्रदेश		हैदराबाद विजयवाड़ा
असम	गुवाहाटी	
बिहार		पटना
दिल्ली		दिल्ली
गुजरात		वडोदरा
गोवा		पणजी
हिमाचल प्रदेश		शिमला
हरियाणा		चंडीगढ़
जम्मू व कश्मीर		जम्मू श्रीनगर
केरल		तिरूवंनतपुरम
कर्नाटक		बेंगलुर
महराष्ट्र	मुम्बई	मुम्बई
उड़ीसा		भुवनेश्वर
पंजाब		चंडीगढ़
राजस्थान		जयपुर
तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	लखनऊ
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	कलकत्ता

Rationalisation of Medical Services Suggested by AIIMS

974. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the All India Institute of Medical Sciences has suggested rationalisation of medical services in the country and to adopt a three-tier system for providing medical facilities to the people at the village and district levels;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have examined the suggestions made by the AIIMS; and

(d) if so, the steps being taken by Government to implement those suggestions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) to (d) The three-tier system of rural health infrastructure in the village level has been adopted from the 5th Five Year Plan onwards. The system comprises of Sub-centres, Primary Health Centres and Community Health Centres established on the basis of population norms. The services provided by the infrastructure include preventive, promotive and curative health care to the people dwelling in the area. The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) has not made any specific suggestion in this regard.

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्तता

975. **श्री एस.एस. सुरजेवाल**:

श्री अजीत जोगी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों की अनुपलब्धता, अपर्याप्त प्रसव सुविधाओं और डाक्टरों/चिकित्सा अधिकारियों की कमी के संबध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं,

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधाओं की कमी के क्या कारण है, और

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?